भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 6436
गुरुवार, 2 अप्रैल, 2026/12 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के अंतर्गत किफायती क्षेत्रीय हवाई संपर्क

6436. श्रीमती मालविका देवीः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्री तापिर गावः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री रोडमल नागरः
श्री भर्तृहरि महताबः
डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का किफायती क्षेत्रीय हवाई संपर्क के माध्यम से अतिरिक्त टियर-2 और टियर-3 शहरों और सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने के लिए उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना का और विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, साथ ही आगामी चरणों में प्रचालनशील किए जाने वाले अतिरिक्त विमानपत्तनों, हेलीपोर्टों और जल-एयरोड्रोमों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान सत्र के दौरान मानपुर हवाई पट्टी से नियमित उड़ानें शुरू करने का विचार है; और
(घ) क्या सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत विशेषकर व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (बीजीएफ) और हवाई कंपनियों की सहभागिता के संबंध में मार्गों की प्रचालनगत संधारणीयता संबंधी कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): सरकार ने अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए 120 नए गंतव्यों को जोड़ने हेतु हाल ही में एक संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी है। यह योजना पर्वतीय, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाईअड्डों को भी सहयोग प्रदान करेगी।

मानपुर (अबू रोड) हवाईपट्टी के लिए हवाई संपर्क के किसी भी वैध प्रस्ताव पर योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

(घ): विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान "क्षेत्रीय संपर्क योजना का मूल्यांकन अध्ययन" नामक एक मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया था। इस अध्ययन में स्पष्ट लक्ष्यों, क्षेत्रीय बाजार स्थितियों के आधार पर बेहतर मार्ग चयन, क्षेत्रीय संपर्क निधि (आरसीएफ) के पर्याप्त वित्तपोषण, आरसीएस हवाईअड्डों के लिए व्यवहार्यता आकलन, क्षमता निर्माण और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ सुदृढ़ समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

******